## Proposed merger of Bhartiya Mahila Bank with SBI

**श्री अली अनवर अंसारी** (बिहार): महोदय, भारतीय महिला बैंक भारतीय उद्योग जगत में अपनी तरह का पहला बैंक है। इस की स्थापना नवम्बर, 2013 में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन अब इस का नामो-निशान मिटाकर इस का एसबीआई में merger किया जा रहा है। महोदय, अच्छी बात है कि वित्त मंत्री जी भी यहां हैं। महोदय, 104 शाखाओं के 550 कर्मचारियों वाली भारतीय महिला बैंक की न सिर्फ पहचान खत्म की जा रही है, बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के उद्देश्य पर भी ग्रहण लग गया है क्योंकि दूसरे सरकारी बैंकों की नौकरियां छोड़कर अनेक महिला कर्मचारियों/अधिकारियों ने इस बैंक को इसी उद्देश्य से join किया था। वे आज सरकार से आश्वासन चाहते हैं कि एसबीआई में merger के साथ ही वेतन भत्ता, प्रोन्नति की वे तमाम सुविधाएं उन्हें मिलेंगी जो एसबीआई के कर्मचारियों/अधिकारियों को मिलती है। मगर कोई उन्हें ऐसा आश्वासन नहीं दे रहा है, इसलिए वे अपने साथ एसबीआई में संभावित दोयम दर्जे के सलूक को लेकर बहुत चिंतित हैं।

महोदय, निर्भया कांड के बाद इस बैंक की स्थापना की गई थी। इस बैंक में अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों पर साठ प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हैं। इस बैंक ने निर्भया स्कीम से लेकर एसिड अटैक की शिकार महिलाओं को लोन देने, लड़कियों के लिए education loan देने, महिला उद्यमियों के लिए पुरुष उद्यमियों से कम ब्याज पर लोन देने और महिला मंथली डिपोज़िट स्कीम आदि योजनाओं में काफी सराहनीय काम किया है। "अटल पेंशन योजना" में इस बैंक को, देश भर के सभी सरकारी बैंकों में तीसरा स्थान मिला है। ऐसा लगता है कि इस सरकार पर हर तरह की क्षेत्रीय पहचान और विविधता को समाप्त करने की धुन सवार है। हमारी सरकारों ने महिलाओं को संसद और विधान सभाओं में 35 प्रतिशत आरक्षण देने से लेकर न जाने कैसे-कैसे वादे किए, लेकिन उनके ज्यादातर नतीजे अभी तक सिफ़र रहे हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देश में एक ही महिला बैंक है, कम से कम इसको तो बख्श दीजिए। मैं इस पर एक शेर बोलना चाहता हूं,

"हसरतें सब मिट चुकीं, बाकी रहा सिर्फ एक निशां,
इसको जलने दो, चिराग़ उजड़ी हुई मंज़िल का है।"

महोदय, बिहार इसकी मिसाल है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, हमारी पार्टी की सरकार ने, वहां पर जिस तरह से महिलाओं का सशक्तीकरण किया है, वह सबके समक्ष है। नीतीश जी की सरकार ने शराबबंदी से लेकर, महिलाओं को तमाम नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने, महिलाओं को नगर निकाय पंचायत चुनावों में 50 प्रतिशत तक आरक्षण देकर एक नज़ीर पेश की है, एक मिसाल पेश की है। देश को इसको भी देखना चाहिए। महिलाओं का एक ही बैंक है, चूंकि अब आप इसको भी खत्म कर रहे हैं, तो वित्त मंत्री जी, कम से कम कुछ आश्वासन तो दे दें।

**श्री पी. एल. पुनिया** (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

**डा. अनिल कुमार साहनी** (बिहार): उपसभापति जी, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

**श्री राम नाथ ठाकुर** (बिहार): उपसभापति जी, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

**श्री शमशेर सिंह डुलो** (पंजाब): उपसभापति जी, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

**श्रीमती कहकशां परवीन** (बिहार): उपसभापति जी, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूं।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

**Concern over the increasing incidents of attacks by *Gau Rakshaks* in various parts of the country**

**श्री सीताराम येचुरी** (पश्चिमी बंगाल): उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। मैं यहां पर एक बहुत ही गंभीर सवाल उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब गौरक्षा के नाम पर इंसानों की जान ली जाती है, तब इसका तीव्र खंडन करते हैं। आखिरकार, प्रधान मंत्री जी उसके बारे में कुछ बोले। वे देर से बोले, लेकिन क्या बोले? वे बोले, "दलितों को मत मारना, मारना है तो हमें मारो" सर, यह डायलॉग हर दूसरी हिन्दी फिल्म में आता है। जब मां कहती है, "बच्चे को बख्श दो, मुझे मार दो।" वह मां कौन है, मतलब एक्टर कौन है, हम सभी लोग वह भी जानते हैं। What is the meaning of saying, "Don't attacks the *dalits*"? Is that the license to attack the non-*dalits*? Is that the license to attack our religious minorities? Remember, in the name of this *Gau Raksha* business, the first person to have died, who has been killed, was Akhlaq and, therefore, this is an issue on which we have been asking the Prime Minister repeatedly standing here. I have been requesting the Prime Minister, for once, please assure us in the House, and, through us, the people of the country, that his Government, this Government, will abide by the rule of the law. If there are people violating the law, action will be taken against them. That assurance, unfortunately, has not come till date. What we want is, what the action that is going to be taken is. Sir, this reminds us one of the Machiavellian dictums, when Machiavelli tells the Prince how to win the hearts of the people. One of the dictums is, "First show the people the worst that is possible under your rule; then proceed with restraint not to do that and people will heave a sigh of relief and say that what a great benefactor he is." What is happening and what the Prime Minister is saying are totally unrelated. We want this assurance from this Government that the law of the land will be protected and action will be taken against those violating this law of the land. That assurance, unfortunately, has not come. The reason why I am raising this issue is that in the name of cow vigilantism today, there is havoc that is being spread in the country; innocent people's lives have been taken away, and we know how the *dalits* are being attacked. So, keeping this in mind, I want, through you, to tell this Government to give that assurance. Once let the Prime Minister come and say in Parliament that those who violate law in our country will be proceeded against and action will be taken. That assurance has not come and that must come now, and that is why I have raised this issue. This cow vigilantism must be stopped now.